International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9, Issue 3, March - 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

21वीं सदी में दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) : समस्याएँ एवं संभावनाएँ

डॉ. संगीता विजय[1*]
श्रीमती दीपिका शर्मा[2**]

प्रस्तावना

आधुनिक युग विकास एवं तकनीकी के युग में आत्मनिर्भर विकास एवं अस्तित्व की कल्पना सम्भव नहीं है। आपसी सहयोग ही शान्ति, आर्थिक विकास, प्रतिरक्षा, लोकतंत्र एवं मानवाधिकारों के संरक्षण की दिशा में सशक्त माध्यम हो सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिज पर अनेकानेक क्षेत्रीय संगठन– सैनिक, आर्थिक, राजनीतिक उद्देश्यों के आधार पर अस्तित्व में आये। दक्षिण एशिया या भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के बीच सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग स्थापित करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय संगठन दक्षिण क्षेत्रीय सहयोग संगठन –स्थापित किया गया।

दक्षिण एशिया वह क्षेत्र है जो उत्तर में हिन्दुकुश व हिमालय से लेकर दक्षिण में हिन्द महासागर एवं बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित सुविस्तीर्ण प्रायद्वीप रुपी एक भौगोलिक इकाई है। इस क्षेत्र में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव द्वीप समूह सम्मिलित हैं। जिसमें ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र के संदर्भ में बहुतला व्याप्त है। दक्षिण एशिया क्षेत्र वह क्षेत्र है जो 50 के दशक से पूर्व ब्रिटिश साम्राज्यवाद से त्रस्त रहा, तथा द्वितीय विश्व युद्ध के उपरान्त नवोदित राष्ट्रों के रूप में विकासशील देशों की श्रेणी में जाने गये। जिनके समक्ष कई प्रकार की चुनौतियाँ विद्यमान थी।

1980 में बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक ढांचे की स्थापना का प्रस्ताव रखा। 1985 को ढाका में एक सार्क सम्मेलन रखा गया और सभी देशों को एक साथ आने की बात कहीं ताकि आपसी संबंधों को सुधारा जा सके। दक्षेस के गठन के समय यह निश्चित किया गया कि इस संगठन का निर्माण क्षेत्रीय, सामाजिक व आर्थिक चुनौतियों को हल करने के लिए किया गया है और राजनीतिक मुद्दों और द्विपक्षीय विवादों को इससे दूर रखा जायगा। लेकिन आज सार्क की कार्य प्रणाली

[1*] एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान एवं लोकप्रशासन विभाग, 511,रामानुज आवास, वनस्थली विद्यापीठ (राज.) **मो. 07597965299**

[2**] **शोध छात्रा,राजनीति विज्ञान विभाग,वनस्थली विद्यापीठ (राज.) मो. 9911059018**

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9, Issue 3, March - 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

और इसके सम्मेलनों पर नजर डालने से ज्ञात होता है कि द्विपक्षीय विवादों को इससे दूर नहीं रखा जा सका। भारत इस संगठन का एकमात्र ऐसा सदस्य है जिसकी सीमा चार देशों के साथ सांझी होती है। दक्षेस का सबसे बड़ा राष्ट्र होने के कारण भारत की सकारात्मक भूमिका दक्षेस को सफल बनाने में अधिक हो जाती है। लेकिन इसका ज्यादा सक्रियता को पड़ौसी देश संदेह की दृष्टि से देखते है।

यद्यपि दक्षेस द्वारा क्षेत्र के देशों के बीच में सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग स्थापित करने की दिशा अनेक कार्य किए गए। किन्तु दक्षिण एशिया के देशों में ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र के संदर्भ में व्याप्त बहुतला एवं विवादों, संदेहों तथा अविश्वास की प्रवृत्ति के कारण सार्क के सामने कई चुनौतियाँ भी खडी हैं। प्रस्तुत लेख में दक्षेस के सामने आने वाली समस्याओं एवं चुनौतियों को रेखांकित करते हुए उनके समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

दक्षेस संगठन की कार्य प्रक्रिया

दक्षेस संगठन के कार्यक्रम मुख्यतः शिखर सम्मेलन हेतु सचिव एवं मंत्रि–स्तरीय समिति की बैठक में प्रस्तावित होती है एवं अंतिम रूप में शिखर सम्मेलनों में स्वीकार किये जाते हैं। कुछ कार्यक्रम संवेदनशील होते हैं एवं तैयारी समिति स्वयं निर्णय न लेकर पक्ष–विपक्ष पर विचार करते हुए अंतिम निर्णय हेतु शिखर सम्मेलन पर छोड़ देती है। जैसे–वीजा में छूट, तटकर छूट आदि शिखर सम्मेलनों में प्रस्तावों पर उदारता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण से विचार किया जाता है ताकि सहमति पर सोचा जा सके।

आरंभ में शिखर सम्मेलनों का आयोजन काफी उत्साह भरे परिवेश में हुआ। भारत–पाक विवाद या अन्य दक्षिण एशियाई देशों के मामले में भारत की रुचि या हस्तक्षेप को लेकर दक्षेस संघ की अल्पायु या व्यापार रोड की आशंकाएं निर्मूल सिद्ध हुईं। 1985 से 1989 तक, 1990 से 1992, 1994 एवं 1996 को छोड़कर शिखर सम्मेलनों का आयोजन वार्षिक ही होता रहा है। जिनमें शासन अध्यक्षों द्वारा निश्चित प्रतिबद्धताएं एवं सहमतियों अभिव्यक्त की। किन्तु उसके बाद शिखर सम्मेलनों के वार्षिक आयोजन में व्यवधान आते रहे। पिछले दो दशकों में मात्र आठ (2002, 04,, 05, 07, 08, 10, 11, 14) शिखर सम्मेलन ही सम्पन्न हुए हैं। पिछले छह वर्षों में एक भी शिखर सम्मेलन नहीं हुआ है। 2016 में 19वां शिखर सम्मेलन पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होना था किन्तु उरी में भारतीय सेना पर आतंकवादी हमले के कारण भारत समेत कई देशों के मना करने पर सम्मेलन रद्द हो गया। उसके बाद भारत–पाक सम्बंधों में तनाव एवं उग्रता के

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9, Issue 3, March - 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

कारण क्षेत्र में अविश्वास एवं भय का वातावरण बना हुआ है। परिणामतः दक्षेस की गतिविधियों पर प्रश्न–चिह्न लग गया।

दक्षेस का 19वां शिखर सममेलन 2016 में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आयोजित होना था, लेकिन 18 सितम्बर को उरी में भारतीय सेना पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने इसमें शामिल होने से इन्कार कर दिया था। इसके बाद बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान ने भी शामिल होने से इन्कार कर दिया था, जिसके बाद सम्मेलन को रद्द कर दिया गया। 20वें दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग शिखर सम्मेलन का आयोजन पाकिस्तान में होना था। 2016 में 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन भी पाकिस्तान में किया जाना था लेकिन भारत समेत कई देशों के मना करने पर यह सम्मेलन रद्द करना पड़ा था। पिछले दो सालों से सार्क सम्मेलन का आयोजन नहीं हो सका है और भारत अगर इस साल भी सार्क सम्मेलन का बहिष्कार करता है तो लगातार तीसरे साल भी ये सम्मेलन रद्द हो सकता है।

दक्षेस की गतिविधियाँ– शिखर सम्मेलन, बैठकें तथा वार्ता –का आयोजन एवं संचालन में गत दो–तीन दशकों से सामान्य रुप से नहीं हो पा रहा है। दक्षेस की गतिविधियों में आने वाली समस्याओं एवं चुनौतियों को – राजनीतिक, आर्थिक, आतंकवाद संबंधी, सैन्य चुनौती, प्राकृतिक चुनौती आदि में विभक्त कर सकते है। जिसका विवेचन इस प्रकार है–

- **राजनीतिक चुनौतियाँ**

दक्षिण एशियाई देशों के मध्य विवादित राजनीतिक समस्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं। नेपाल व भूटान को छोड़कर ब्रिटिश शासन के 150 वर्षों के शासन ने कई विरोधाभासों को जन्म दिया। पड़ोसी देशों की ताकतों ने भारत का जब–जब समर्थन किया तब–तब सम्बंधित देश की सत्तावादी ताकतों को भारतीय समर्थन रास नहीं आया। उपनिवेशकाल में ब्रिटिशों ने यहां एक इकाई के रूप में काम किया और दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय राजनीति में सीमा विवादों ने सम्बंधों को बहुत प्रभावित किया है। इन देशों का विश्व की ओर देखने का दृष्टिकोण भी अलग–अलग है। राष्ट्रीय क्षमता और शक्ति की दृष्टि से भारत अपने सभी पड़ोसियों से इस क्षेत्र व जनसंख्या में अधिक शक्तिशाली है। भारत की विशालता पड़ोसियों में भौगोलिक लघुपन को जन्म देती है।

भारत और उसके पड़ोसियों के बीच तीन स्तरों पर सम्बंध पाये जाते हैं पहले स्तर पर भूटान व मालदीव जैसे देश हैं जो भारत से अपनी विषमता को अपना प्रारंभ मान चुके हैं। दूसरे स्तर पर नेपाल,

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9, Issue 3, March - 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे अंतर को अपूर्णीय मानते हैं और मुद्दों के प्रति संतुलित रहने की कोशिश करते हैं। तीसरे स्तर पर पाकिस्तान है जो भारत से बराबरी का प्रयास करता है। भारत के प्रति पाकिस्तान का रुख दक्षेस की सफलता में बाधा है।

- **आर्थिक चुनौतियां**

दक्षिण एशिया एक ऐसा क्षेत्र है जहां दुनिया की सबसे जीवंत अर्थव्यवस्था है फिर भी दक्षिण एशिया के देशों में वास्तविक व्यापार और संभावित व्यापार का अंतर 2001 से ही लगातार बढ़ रहा है। संरक्षणवादी नीतियों, राजनीतिक इच्छाशक्ति और व्यापक विश्वास की कमी के कारण दक्षिण एशिया में अंतर क्षेत्रीय व्यापार निम्न स्तर का है। 2018 में भारत का अपने पड़ौसियों के साथ व्यापार, 36 बिलियन अमेरिकी डालर तक पहुंच गया था। इस क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा बाजार बांग्लादेश है। इसके बाद नेपाल और श्रीलंका और सबसे अधिक मूल्य का आयात म्यांमार, श्रीलंका और बांग्लादेश से आता है। 2018 के आंकड़ों के अनुसार भारत व्यापार में लाभ की स्थिति में है। बांग्लादेश 7.6 बिलियन अमेरिकी डालर, नेपाल 6.8 बिलियन अमेरिकी डालर है। भारत और पाकिस्तान के बीच 2017–18 के मध्य 2.4 अरब डालर का व्यापार हुआ जबकि दोनों देशों के बीच लगभग 38 अरब डालर के व्यापार की क्षमता मौजूद है। पाकिस्तान को छोड़कर देखों तो भारत का अपने पड़ोस के साथ व्यापार लगातार बढ़ रहा है। लेकिन इनके बाद भी सार्क देशों को आपसी कारोबार बढ़ाने की जरूरत है।

आतंकवाद चुनौती

आतंकवाद से निपटने के लिए 12वें सार्क सम्मेलन में आतंकवाद सम्बंधी प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किये गये और उम्मीद की गयी थी कि सभी सदस्य राष्ट्र इस प्रोटोकाल का समर्थन करेंगे। लेकिन इसके बाद भी भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं उससे लगता है कि सकारात्मक बदलाव आने की संभावना न के बराबर है। 2019 की घटनाओं ने तय किया कि 2020 का साल भारत और पाकिस्तान के लिहाज से कैसा रहेगा। 2019 में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश–ए–मुहम्मद ने पुलवामा का आत्मघाती हमला किया इससे दोनों देशों के रिश्तों में गिरावट का दौर आरंभ हो गया था। अगस्त 2019 में हुआ दूसरा क्रांतिकारी परिवर्तन जिसने पाकिस्तानी सरकार को झकझोर कर रख दिया। सार्क की विदेश मंत्रियों की बैठक में आतंकवाद को एक वैश्विक चुनौती माना गया।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9, Issue 3, March - 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

- **सतत् विकास एक चुनौती**

दक्षिणी एशिया में पूरे विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 35% स्थित है पर जनसंख्या की बात कहें तो विश्व की कुल जनसंख्या का एक चौथाई भाग ही यही निवास करता है। दक्षिणी एशिया में विश्व के 30% से अधिक निर्धन व्यक्ति निवास करते हैं और यह क्षेत्र आर्थिक और पर्यावरण सम्बंधत चुनौतियों का वर्षो से सामना करता आया है। सतत् लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 2015 में एक सूची तैयार की गई थी जिसमें 17 लक्ष्यों का वर्णन किया गया और 2030 तक सभी सदस्य देशों को यह लक्ष्य पूरा करना था। भारत के प्रदर्शन की बात करें तो इसका प्रदर्शन दक्षिणी एशिया के देशों में सबसे बुरा है। चारों ओर स्थल से घिरे और विकास के निम्न स्तर वाले भूठान और नेपाल जैसे देशों में भी इस मामले में अच्छी रैंक प्राप्त की थी। अधिकांश दक्षिण एशियाई देशों ने अत्यधिक गरीबी को जड़ से उखाड फेंकने के लिए बहुत ही अधिक प्रयास किया है। लेकिन ये देश उद्योग, नवाचार, लिंग, समानता, शिक्षा सम्बंधी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सदस्य देशों का आपस में समन्वय जरूरी है।

- **सैन्य चुनौती**

भारत अपने सभी पड़ोसी देशों में सैन्य शक्तियों को देखते हुए सबसे मजबूत है। अगर हम भारत और पाकिस्तान की सैन्य ताकतों को देखें तो भारत अधिक शक्तिशाली दिखाई देता है। थल सेना की क्षमता के मामलों में पाकिस्तान भारत से बहुत पीछे है। भारत की सैनिक क्षमता 12,000235 है जबकि पाकिस्तान के पास 6,20,000 ही सैनिक हैं। भारत के पास कॉम्बैट टैंक 4,426 हैं वहीं पाकिस्तान के पास 2924 है। वायुसेना की बात करें तो यहां भी भारत पाकिस्तान से बहुत आगे नजर आता है। वर्तमान में भारत के पास 2102 विमान हैं वहीं पाकिस्तान के पास 951 विमान हैं।

भारतीय भौगोलिक स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण है। इसके एक ओर चाइना है जिससे भारतीय सीमा विवाद प्रारंभ से ही उलझा रहा। स्वतंत्रता के बाद चाइना ने युद्ध प्रयासों के बाद भारत के भू–भाग को अपने अधीन कर लिया लेकिन भारत के सीमावर्ती देशों बर्मा, बांग्लादेश, नेपाल से भारत को कोई सैन्य चुनौती नहीं है।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन 'दक्षेस' क बारे में पिछले कुछ वर्षो में यह धारणा व्यक्त की जाने लगी है कि यह संगठन शिथिल हो गया है तथा एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में इतना प्रभावशाली नहीं

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9, Issue 3, March - 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

हो सकता है। जिस प्रकार से दक्षेस देशों द्वारा शिखर सम्मेलन के स्थगन की घोषणा की जाती है उससे तो दक्षेस की राह और कठिन होती जा रही है।

इस राजनीतिकरण का सबसे ज्यादा संकट दक्षेस के शिखर सम्मेलनों में देखने को मिला है। अगर इसके घोषणा–पत्र में देखा जाए तो यह लिखा गयाथा कि दक्षेस के शासनाध्यक्ष वर्ष में एक बार या अधिक बार शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे लेकिन दक्षेस इसकी न्यूनतम पूर्ति भी नहीं कर पाया है। आतंकवाद का मसला सबसे पहले दक्षेस मंच पर श्रीलंका ने उठाया था। सभी देशों ने इस बात का समर्थन किया था कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सामूहिक प्रयास किये जाने चाहिए। पाकिस्तान भी इस घोषणा में सम्मिलित था। एक ओर तो पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हुआ नजर आता है वहीं दूसरी ओर उसकी सरजमीं पर ही आतंकवाद पनप रहा है।

इन सब बातों के बावजूद भी दक्षेस के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। दक्षेस के सभी देश भारत के पड़ोसी जरूर हैं लेकिन उनमें से भारत के सिवाय किसी की सीमा दूसरे से नहीं मिलती। दक्षेस के सामने एक चुनौती यह भी है कि सामाजिक–आर्थिक मुद्दे जो कि उसके गठन के मूल आधार थे कहीं–न–कहीं वो दूर जा रहे हैं।

दक्षेस को समय रहते सामाजिक, आर्थिक, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि पड़ोसी देशों की यह सोच बनती जा रही है कि भारत और पाकिस्तान अपने सीमा सम्बंधी विवादों में इतना घिर गये हैं कि दक्षेस को उन्होंने दरकिनार कर दिया है।

दक्षेस का सबसे बड़ा राष्ट्र होने के कारण भारत की भूमिका बनती है कि वह दक्षेस को सफल बनाने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाए। भारत की नीति आरंभ से ही संभलकर चलने वाली रही है। क्योंकि उसको लगता था कि वो अगर ज्यादा सक्रिय हो जाएगा तो पड़ोसी देश उसको संदेह की दृष्टि से देखेंगे। इसलिए भारत पहले प्रतीक्षा करो, देखा और तब हाथ काम में लो की नीति पर चलता रहा। अब जरूरी है कि भारत को अपनी व्यापक भूमिका निभानी पड़ेगी और बहुक्षीय समझौतों को महत्व देना होगा दक्षेस के अन्य राष्ट्र भी भारत से अपेक्षा कर रहे हैं कि वह उन्हें नेतृत्व प्रदान करे और सभी सदस्य राष्ट्र सामूहिक रूप से मिलकर चुनौतियों का सामना करें।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9, Issue 3, March - 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

निष्कर्ष

दक्षेस के सामने आने वाली समस्याओं और चुनौतियों को कम करके नहीं आंका जा सकता, लेकिन हम दक्षिण एशिया और सार्क को आधा भरा गिलास के रूप में देख सकते हैं। जबकि निराशावादी इसको आधा खाली गिलास के रूप में देखते हैं। दक्षेस का सबसे बड़ा राष्ट्र होने के कारण दक्षेस को सफल बनाने में भारत की भूमिका बढ़ जाती है। हमें अधिक जनसंख्या, अत्यधिक गरीबी और अंतहीन छोटे–मोटे झगड़ों पर निराश होने की जरूरत नहीं है। इसकी बजाय हमें क्षेत्र पर अत्यधिक युवा और बदलाव वाला तथा सकारात्मक दृष्टिकोण, चालू सुधार, विशाल बाजार तथा लाभ के नजरिए से ध्यान देना चाहिए ताकि दक्षेस को अपना वाजिब स्थान मिल सके। सार्क के सभी देशों को ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए ताकि बुरी राजनीति अच्छी अर्थव्यवस्थाओं पर हावी न हो सकें और हमें यह मानकर चलना चाहिए कि दक्षेस के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना हम सबको मिलकर करना होगा। हम पास–पास नहीं हैं हम साथ–साथ हैं।

Refrences: -

SAARC Challenge and Prospects, "Dr. Bajrang, Highbrow Scribes Publication, 2018 Nov.

- Inter State Conflics and issues in South Asia challenges and prospects for sarcs, "Emanual Nahlar Kalpaz Publication, Jan 2019
- Regional Coporation in South Asia, "Nidhi Sharma, Kalpaz Publication, March. 2019
- India and Sarc Engagements, "Goyal O.P., Gyan book Publishes.
- Thirty years of Sarc – Society, Culture and Development, "Rajiv Kumar, Omita Goyal, Sage Publication, Feb 2019 .
- India's Relation with her Neighbour, " Trivedi Romesh, Isha Publishing, 2016